RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 03 MARCH TO 09 MARCH 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 28 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

बढ़ती कीमतों के बावजूद अगले साल तक 10 फीसदी बढ़ जाएगी पेट्रोल-डीजल की मांग Page 2

मध्यप्रदेश का 2021-22 का बजट 2,41,375 करोड़ रुपये का, कोई नया कर नहीं Page 5

दिवाला प्रक्रिया वाली कंपनियों के खिलाफ 'चेक बाउंस' का मामला नहीं चल सकता : न्यायालय Page 7

editoria!

वित्तीय सुगमता जरूरी

महामारी से पैदा हुई मंदी और मुद्रास्फीति से जूझती अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे बेहतरी की ओर अग्रसर है. इस प्रक्रिया में स्टार्टअप और वित्तीय तकनीक पर आधारित उद्यमों की अहम भूमिका है. भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए भी ऐसी कारोबारी पहलों को बढ़ावा देना जरूरी है. इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे उद्यमों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंक विशेष प्रयास करें. बैंकिंग तंत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र भी शामिल है. तकनीक के विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता तथा उद्यमशीलता बढ़ने से गांवों व कस्बों में नवाचार और कारोबार में बढ़ोतरी की गुंजाइश बढ़ी है. लेकिन बैंकों के कामकाज की सीमाओं की वजह से ऐसी कोशिशों के लिए धन जुटाना मुश्किल काम है. प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकों से कहा है कि वे छोटे शहरों और गांवों की आकांक्षाओं समझें तथा उन्हें आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनायें. हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, जिसका अधिकांश गांवों व कस्बों में बसता है. यदि युवाओं को अपने कारोबारी सपनों को अमली जामा पहनाने के लिए समुचित वित्त की व्यवस्था होगी, तो रोजगार के नये अवसर भी बनेंगे तथा स्थानीय विकास को गति भी मिलेगी. कोरोना महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के साथ सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों से संबंधित नीतियों में भी बदलाव किया था. इन उद्यमों को 2.4 ट्रिलियन रुपये का ऋण भी मुहैया कराया गया है. स्थानीय उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रमुख तत्व है. सरकार ने आर्थिक सुधारों को गति देकर अर्थव्यवस्था के विस्तार का रास्ता खोल दिया है. लेकिन इस विस्तार के लिए आवश्यक है कि बैंक उद्यमों और कारोबारों को कर्ज दें. बीते वर्षों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़ी मात्रा में पूंजी दी है ताकि उन्हें कर्ज देने में दिक्कत न आये. अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट में भी पूंजी मुहैया कराने के लिए आवंटन किया गया है. इसे आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को भी आगे आना होगा. एक-डेढ़ दशक पहले बैंकों द्वारा आक्रामक ढंग से कर्ज बांटने की वजह से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकट भी बैंकों के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन, जैसा प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है, सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक कदम उठाये हैं. रिजर्व बैंक ने भी बैंकों के प्रबंधन और कामकाज को दुरुस्त करने के लिए नियम बनाये हैं. ऐसे में बैंकों को नवाचार और नये उद्यमों के लिए धन देने में संकोच नहीं होना चाहिए. पूंजी जुटाने में होनेवाली परेशानियों से ऐसे कारोबारों को शुरू में ही झटका लग सकता है और उनकी संभावनाएं कुंद हो सकती हैं. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की सलाह के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र की ओर से सकारात्मक पहल होगी.

कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं OPEC+ देश

क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीज़ल?

नई दिल्ली। इस सप्ताह होने वाली बैठक में OPEC+ समूह कच्चे तेल (Crude Oil) का उत्पादन बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। इस फैसले से कच्चे तेल के भाव कम होने की उम्मीद भी बढ़ेगी। खासकर, भारत के लिए, जहां पेट्रोल-डीज़ल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। बैठक से पहले इस समूह में अधिकतर देशों का मानना है कि अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो तेल की खपत भी बढ़ेगी। हालांकि, कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में ध्ध्ध्ध् देशों की इस समूह द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और रूस में मतभेद की भी बात कही गई है। दरअसल, उत्पादन बढ़ाने को लेकर सऊदी अरब का नज़रिया अब भी सतर्क दिखाई दे रहा है, जबकि रूस उत्पादन बढ़ाने के मूड में है. इन सबके बीच गुरुवार को होने वाले बैठक में क्रूड ऑयल का उत्पादन 15 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है।

पिछले साल तेल उत्पादकों को उठाना पड़ा था नुकसान

अगर बैठक में तेल उत्पादक देशों के बीच प्रोडक्शन बढ़ाने की सहमति बनती है तो इससे यह भी साफ हो जाएगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब कोरोना की मार से उबर रही है। क्रूड उत्पादक देशों के लिए पिछला एक साल चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्हें इतिहास में सबसे बड़े आउटपुट कटौती तक का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन के बाद दुनियाभर में ईंधन की मांग रिकॉर्ड स्तर पर कम हो चुकी थी। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में इन देशों को फायदा भी हुआ है। खासकर तब, जब कच्चे तेल का भाव एक बार फिर 60 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने में कामयाब रहा है।

तेल उत्पादकों के लिए अब स्थिति बेहतर

ओपेक सचिव जनरल मोहम्मद बारकिंदो के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा है, 'वैश्विक आर्थिक रिकवरी और ऑयल मार्केट में संभावनों से पता चलता है कि स्थिति अब बेहतर हो रही है.' उन्होंने कहा कि पिछले साल जिस तरह से अनिश्चितताओं के बीच बाजार इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अब खत्म हो चुकी है।

गुरुवार को बैठक में इन दो मुद्दों पर होगी चर्चा

मंगलवार को भी लगातार चौथे दिन कच्चे तेल के दाम में नरमी देखने को मिली है। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 1.6 फीसदी तक कम होकर 62.70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। हालांकि, पिछले साल की सामान अवधि की तुलना में यह अभी भी करीब 20 फीसदी अधिक है। इस सप्ताह होने वाली बैठक में ओपेक प्लस देशों का समूह दो बातों पर प्रमुखता से चर्चा करने वाला है। इसमें पहला तो यह है कि अप्रैल में ये देश एक साथ मिलकर प्रति दिन 5 लाख बैरल तक उत्पादन बढ़ाएंगे या नहीं। जबकि, दूसरा मुद्दा यह भी होगा कि सऊदी अरब कैसे अतिरिक्त सप्लाई कटौती को कम करेगा। क्या यह चरणबद्ध तरीके सो होगा? फरवरी और मार्च के लिए सउदी अरब ने 10 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त सप्लाई घटाने का फैसला लिया था।

पिछले साल करनी पड़ी ऐतिहासिक कटौती

सऊदी अरब अब जो भी फैसला ले, एक बात तो तय है। कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में पिछले साल अगस्त के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई बूस्ट मिलने वाला है। पिछले साल अप्रैल में तेल उत्पादक देशों को उत्पादन में हर दिन 97 लाख बैरल तक की कटौती करनी पड़ी थी। अगर फरवरी से जून के बीच ये देश 24 लाख बैरल प्रतिदिन तक का भी उत्पादन बढ़ाते हैं तो भी वैश्विक स्तर पर कई देशों को फायदा होगा और पिछले साल हुए नुकसान की भरपाई करने में मिल सकेगी।

नर्चरिंग नेबरहूड्स चैलेंज कोहॉर्ट के लिए शीर्ष 25 शहरों में इंदौर चयनित

चयनित 25 कोहॉर्ट शहरों को अपने प्रस्तावों का परीक्षण करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिये अगले छह माह तक सहयोग और तकनीकी सहायता मिलेगी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन ने बर्नार्ड वैन लीएर फाउंडेशन (BvLF) और तकनीकी भागीदार डब्ल्यूआरआई इंडिया के साथ गठबंधन में 'नर्चरिंग नेबरहूड्स चैलेंज' कोहॉर्ट के लिये 25 चयनित शहरों की घोषणा की है। यह चैलेंज तीन वर्ष की एक पहल है, जिसका लक्ष्य सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत बच्चों के लिये अनुकूल आस-पड़ोस बनाने को सहयोग देना है। इस चैलेंज के पहले स्टेज में सिटी एजेंसियों के आवेदनों के लिये ओपन कॉल था और वह 7 फरवरी, 2021 को बंद हो गया था। भारत के 63 शहरों ने सार्वजनिक स्थान, परिवहन और सेवाओं तक पहुँच में आस-पड़ोस के स्तर के पायलट प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव देते हुए आवेदन प्रस्तुत किये थे, ताकि छोटे बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को समृद्ध बनाया जा सके। आवेदक शहरों की सूची में से मूल्यांकन समिति ने आवेदनों की मजबूती के आधार पर पच्चीस (25) शहरों का चयन किया। 'नर्चरिंग नेबरहूड्स चैलेंज' कोहॉर्ट के लिये इन शहरों का चयन हुआ है: अगरतला, बेंगलुरू, कोयंबटूर, धर्मशाला, ईरोड, हुबली-धारवाड़, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, कोटा, नागपुर, राजकोट, रांची, रोहतक, राउरकेला, सलेम, सूरत, तिरूवनंतपुरम, तिरूपुर, उज्जैन, वडोदरा और वारंगल। शहरों ने पायलट प्रोजेक्ट्स की एक विविधतापूर्ण श्रृंखला प्रस्तावित की थी, जैसे आवासीय आस-पड़ोस में टॉडलर-फ्रेंडली वॉकिंग कॉरिडोर्स, शहरी झुग्गियों में रहने वाले छोटे बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के लिये सुरक्षित परिवहन और बाल्यावस्था सेवाएं, प्रकृति के साथ क्रीड़ा और संवेदी उत्तेजन के अवसर बढ़ाना और स्कूली घंटों के बाद सरकारी स्कूलों के मैदानों के भीतर की उपयोग में कम लाई जाने वाली खुली जगहों को सार्वजनिक खेल स्थलों के रूप में अपनाना। गलियों और खुली जगहों के अलावा, अन्य प्रस्तावित पायलट्स का लक्ष्य सरकारी कार्यालय परिसरों, बस शेल्टर्स और ट्रांजिट हब्स में बाल्यावस्था सुविधाओं की जरूरत को सम्बोधित करना, आंगनवाड़ियों का न्यूट्रीगार्डन्स और आयु के अनुसार खेल उपकरणों के साथ विकास करना और शेड, सीटिंग और लैक्टेशन क्युबिकल्स के साथ पीएचसी के लिये आउटडोर वेटिंग एरियाज का कायाकल्प करना है।

पेट्रोल 45 रुपये लीटर तक हो सकता है सस्ता, डीजल का दाम भी होगा कम, मोदी सरकार कर रही है विचार

नई दिल्ली। एजेंसी

आने वाले दिनों में अगर आपको पेट्रोल-डीजल 45 रुपये लीटर मिलने लगे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये लीटर के पार पहुंचे पर मोदी सरकार इसके दाम कम करने पर शिद्दत से विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले, जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर ना पड़े और आम जनता को भी राहत मिल जाए।

पहला रास्ताः केंद्र सकरार उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारें घटाएं वैट

दुनिया का इंजन अभी भी पेट्रोल-डीजल से ही चल रहा है। इसके दाम में बदलाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है चाहे वह वाहन चलाता हो या नहीं। कच्चे तेल के दाम में लगातार वृद्धि होने से भारत में सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही हैं। फरवरी में ही दोनों ईंधन करीब 5 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं। वहीं कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी है, जिसने घरेलू बाजार यानी भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। भारत के लोगों को तेल की महंगाई का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स की वजह से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।

इन राज्यों ने घटाया वैट

इस बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार को एक्साईज ड्यूटी और राज्य सरकारों को वैट कम करना होगा। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और मेघालय सरकार ने पहले ही वैट घटाकर आम जनता को थोड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे पहले राजस्थान ने घटाया था। राजस्थान में 29 जनवरी को वैट 38 फीसद से 36 फीसदी किया गया था। असम ने 12 फरवरी को 5 रुपये टैक्स में कम किए, वहीं मेघालय ने सबसे अधिक राहत दी। यहां राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 7.40 रुपये और डीजल पर 7.10 रुपये कम किए। टैक्स की वजह से पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100 फीसद से ज्यादा टैक्स वसूल रही हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा है कि 35 रुपये का पेट्रोल राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है।

दूसरा रास्ताः पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में आए

कुछ दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमण्यम ने पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। सुब्रमण्यम ने हाल में फिक्की एफएलओ सदस्यों के साथभारत परिचर्चा में कहा, ''यह एक अच्छा कदम होगा। इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का आग्रह कर चुकी हैं। वहीं, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझावों पर अगर जीएसटी परिषद अमल करती है तो देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आधी हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय जीएसटी परिषद से पेट्रोलियम उत्पादों को अपने दायरे में शामिल करने का लगातार अनुरोध कर रहा है, क्योंकि इससे लोगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दे चुकी हैं।

पेट्रोल-डीजल के रेट पर ये होगा असर

■जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल-डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती हैं। ■यदि जीएसटी परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना, तो कीमतों में कमी आ सकती है। ■भारत में चार प्राथमिक जीएसटी दर हैं - 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद ■अगर पेट्रोल को 5 फीसद जीएसटी वाले स्लैब में रखा जाए तो यह पूरे देश में 37.57 रुपये लीटर हो जाएगा और डीजल का रेट घटकर 38.03 रुपये रह जाएगा। ■अगर 12 फीसद स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल की कीमत होगी 40 फीसद और डीजल मिलेगा 40.56 रुपये। ■अगर 18 फीसद जीएसटी वाले स्लैब में पेट्रोल आया तो कीमत होगी 42.22 रुपये और डीजल होगा 42.73 रुपये। ■वहीं अगर 28 फीसद वाले स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल 45.79 रुपये रह जाएगा और डीजल होगा 46.36 रुपये।

यहां है दिक्कत

राज्य पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार नहीं हैं। 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। उस समय राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल किया जाता है, तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी।

News यू केन USE

भारत के खिलौना क्षेत्र में निर्यात की व्यापक क्षमता : वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने कहा है कि भारत के खिलौना क्षेत्र में निर्यात की बड़ी क्षमता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के संभावित निर्यातकों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा। वधावन ने सोमवार को 'भारत से खिलौना निर्यात बढ़ाने' पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार नवोन्मेषी और सृजनात्मक तरीकों से खिलौनों संकुलों को प्रोत्साहन देना चाहती है। उन्होंने कहा, ''खिलौना विनिर्माण संकुल राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए जाने चाहिए। इनके जरिये विदेशी कंपनियों को भारत में अपना विनिर्माण आधार स्थापित करने को आकर्षित किया जाना चाहिए।'' सचिव ने खिलौना आधारित पर्यटन, स्थानीय खिलौना बैंक और पुस्तकालय को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाना अच्छा कदम होगा : मुख्य आर्थिक सलाहकार

कोलकाता। एजेंसी

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमण्यम ने पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसपर निर्णय जीएसटी परिषद को करना है। सुब्रमण्यम ने हाल में फिक्की एफएलओ सदस्यों के साथ परिचर्चा में कहा, ''यह एक अच्छा कदम होगा। इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है।'' पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का आग्रह किया है। ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी पर बोझ बढ़ा है। यह विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में एक प्रमुख मुद्दा है। सुब्रमण्यम ने कहा कि मुद्रास्फीतिक दबाव मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की महंगाई की वजह से है।

'इंडियन प्लास्ट टाइम्स' के स्वामित्व एवं अन्य विवरण के संबंध में

घोषणा पत्र

फार्म-4 (नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशक का स्थान	:	इंदौर
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	सचिन बंसल
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	:	हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	-
पता	:	18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	:	सचिन बंसल
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	:	हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	-
पता	:	18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.)
5. प्रधान संपादक का नाम	:	सचिन बंसल
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	:	हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	:	-
पता	:	18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों :	:	नहीं

मैं **सचिन बंसल** एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 03 मार्च 2021

हस्ताक्षर
सचिन बंसल
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

BPCL Disinvestment की प्रक्रिया शुरू होते ही कंपनी के स्टॉक्स 52-Weeks High पर पहुंचे

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के विनिवेश (Disinvestment) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। BPCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (Numaligarh refinery- NRL) में अपनी 61.65% हिस्सेदारी 9875 करोड़ रुपये में बेचने को मंजूरी दे दी है। इससे उत्साहित शेयर बाजार में आज कंपनी के स्टॉक्स 1 साल के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के स्टॉक्स आज BSE पर 4.2% की तेजी के साथ 474.50 रुपये पर खुले और देखते ही देखते 482.40 रुपये के 52-Weeks High पर पहुंच गए। हालांकि, बाद में इसके स्टॉक्स की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी और कंपनी के स्टॉक्स आज 3.24% की तेजी के साथ 470 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि BPCL के प्राइवेटाइजेशन के तहत नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 49% हिस्से का अधिग्रहण ऑयल इंडिया लिमिटेड (IOL) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (Engineers India Ltd) की

कंसोर्टियम करेगी। जबकि, 13.65% हिस्सा असम सरकार को बेचा जाएगा। बिक्री प्रक्रिया 31 मार्च, 2021 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। ब्रेकरेड फर्म Emkay Global ने कहा कि BPCL के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण कदम है और FY21-22 की पहली छमाही में कंपनी की Disinvestment प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। Emkay Global ने BPCL के स्टॉक्स को Buy रेटिंग दिया है। वहीं, एक और ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal Financial Services ने भी इसे बाई रेटिंग दिया और कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइरी की बिक्री से कंपनी अपने कर्ज को कम कर सकेगी। साथ ही कंपनी अपने निवेशकों को 16 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड देने के अलावा प्रति शेयर 38 रुपये इंक्रिमेंटल डिविडेंड दे सकती है।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने पर हो रहा काम

आपको बता दें कि देश के कुल रिफाइनरी क्षमता में BPCL की हिस्सेदारी 15.33% और ऑयल मार्केटिंग के क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी 22% के करीब है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी तेल रिफाइन करने की क्षमता को 30 लाख टन से बढ़ाकर 90 लाख टन प्रति वर्ष करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए कंपनी 22,594 करोड़ रुपये निवेश करेगी। यह परियोजना 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। BPCL के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में NRL का नेट प्रॉफिट 120% बढ़कर 2,777.6 करोड़ रुपये हो गया। जबकि पिछले साल इस अवधि में कंपनी को नेट प्रॉफिट केवल 1,260.6 करोड़ रुपये रहा था।

वृद्धि के राह पर लौटी अर्थव्यवस्था, तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.4 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि के रास्ते पर आ गयी है। कृषि, सेवा और निर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पहले, कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये 'लॉकडाउन' के बीच लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गयी थी। व्यापार और होटल उद्योग में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.7 प्रतिशत की गिरावट आयी। कोरोना संकट का क्षेत्र पर असर अब भी जारी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आलोच्य तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निर्माण क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत जबकि बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। एनएसओ के अनुसार, ''चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में स्थिर मूल्य 2011-12 पर जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपये रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 36.08 लाख करोड़ रुपये थी। यानी जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'' वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एनएसओ के राष्ट्रीय लेखा के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान जताया गया है। जनवरी में एनएसओ ने पहले अग्रिम अनुमान में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान जताया था। आंकड़ों के अनुसार, ''वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्य (2011-12) पर 2020-21 में 134.09 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाने का अनुमान है जो 2019-20 में 29 जनवरी 2021 को जारी पहले संशोधित अनुमान के अनुसार 145.69 लाख करोड़ रुपये था।'' ''वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है जबकि 2019-20 में इसमें 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।'' कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये 'लॉकडाउन' के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 24.4 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। वहीं दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। इससे पहले नवंबर में जारी अस्थायी अनुमान में पहली और दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान - 24.9 प्रतिशत और - 7.5 प्रतिशत था। वास्तविक आधार पर 2011-12 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 85,929 रुपये रहने का अनुमान है जो 2019-20 में 94,566 रुपये थी। यह 9.1 प्रतिशत की गिरावट को बताता है जबकि इससे पूर्व वित्त वर्ष में इसमें 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,27,768 रुपये रही। यह 2019-20 में 1,34,186 रुपये के मुकाबले 4.8 प्रतिशत कम है। एनएसओ ने कहा, ''सरकार ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिये जो कदम उठाये हैं, उसका आर्थिक गतिविधियों के साथ आंकड़ा संग्रह व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है।'' एनएसओ के अनुसार, ''आईआईपी औद्योगिक उत्पादन और सीपीआई खुदरा मुद्रास्फीति जैसे अन्य वृहत आर्थिक संकेतकों के मामले में आंकड़ों को लेकर चुनौतियां रही हैं। इनका उपयोग राष्ट्रीय लेखा के अनुमान में किया जाता है। इसके साथ सरकार द्वारा उसके बाद के महीनों में महामारी के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार को लेकर कदम उठाये जाते हैं, तो उन उपायों का असर होगा और फलतः इन अनुमानों की समीक्षा की जा सकती है।'' वित्त मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर तिमाही में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि यह बताती है कि अर्थव्यवस्था महामारी के पूर्व स्तर पर आ गयी है और पुनरूद्धार का ग्राफ आने वाले समय में तीव्र गति यानी ₹ आकार में उठेगा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि से संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था महामारी पूर्व के वृद्धि के रास्ते पर लौट आयी है। यह पहली तिमाही में जीडीपी में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में शुरू तीव्र गति से पुनरूद्धार के और मजबूत होने को प्रतिबिंबित करता है...।'' इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री ने कहा, ''वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी और जीवीए सकल मूल्य वर्धन दोनों में वृद्धि के लौटने के साथ महामारी संकट के कारण तकनीकी रूप से जो मंदी की स्थिति आयी थी, वह समाप्त हो गयी है। यह हमारे अनुमान के अनुरूप है।'' उन्होंने कहा कि एनएसओ ने तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.4 प्रतिशत और जीवीए में 1.0 प्रतिशत वृद्धि की बात कही है जबकि इक्रा ने 0.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया था। उद्योग मंडल सीआआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि एक बढ़िया संकेत है। यह संकेत देता है कि महामारी संकट के कारण जो पहली छमाही में मंदी की स्थिति बनी थी, वह अब समाप्त हो गयी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के जरिये वृद्धि के लिये जो प्रोत्साहन दिये गये हैं और उत्पादन आधरित प्रोत्साहन पीएलआई समेत अन्य उपायों से वृद्धि में आने वाले समय में तेजी आएगी। डेलॉयट इंडिया के भागीदारी संजय कुमार ने कहा, ''चौथी तिमाही जनवरी-मार्च में वृद्धि दर में और तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि तिमाही के दौरान कई क्षेत्रों खासकर होटल और यात्रा जैसे क्षेत्रों में काफी ढील दी गयी है।'' एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि कोई अचंभित करने वाला नहीं है बल्कि यह दो तिमाही की गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि के रास्ते पर लौटने का संकेत है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही और बेहतर रहने की उम्मीद है। चीन की अर्थव्यवस्था में अक्टूबर-दिसंबर, 2020 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वहीं जुलाई-सितंबर में वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत रही थी। एम्के वेल्थ मैनेजमेंट के अनुसंधान प्रमुख डा जोजफ थामस ने कहा कि इन आंकड़ों में विस्तृत क्षेत्रों में सुधार दिखता है। नारेडकों महाराष्ट्र के संयुक्त सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि जीडीपी में और तीव्र वृद्धि हासिल करने के लिए सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नाइट फ्रैंक इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा कि अर्थव्यवस्था 'सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों से ज्यादातर आर्थिक संकेतकों में सुधार दिख रहा है। ऐसे में तीसरी तिमही में अर्थव्यवस्था के पुनः वृद्धि की रहा पर लौटने में कोई आश्चर्य नहीं है।'

GST को लेकर गुड न्यूज

लगातार 5वें माह कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (GST) का कलेक्शन फरवरी में लगातार पांचवें महीने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि फरवरी में जीएसटी कलेक्शन सात प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। हालांकि, फरवरी के जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जनवरी से कम रहा है। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,19,875 करोड़ रुपये रहा था।

CGST और SGST का कितना रहा हिस्सा

फरवरी में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,13,143 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा 21,092 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का हिस्सा 27,273 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का हिस्सा 55,253 करोड़ रुपये रहा। आईजीएसटी में 24,382 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए। उपकर का हिस्सा 9,525 करोड़ रुपये रहा। इसमें से 660 करोड़ रुपये वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए।

आयात से आया 15 प्रतिशत अधिक रेवेन्यु

वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले पांच माह से जीएसटी राजस्व कलेक्शन में सुधार का रुख दिख रहा है। फरवरी 2021 में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के समान महीने से सात प्रतिशत अधिक रहा है। बयान में कहा गया, ''माह के दौरान वस्तुओं के आयात से राजस्व 15 प्रतिशत ऊंचा रहा। घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले साल के समान महीने की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक रहा।''

बढ़ती कीमतों के बावजूद अगले साल तक 10 फीसदी बढ़ जाएगी पेट्रोल-डीजल की मांग, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली। देश में एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में भारत के अंदर पेट्रोल-डीजल और अन्य ईंधन की मांग 215.24 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। पेट्रोलियम मंत्रालय के प्लानिंग एंड एनलेसिस सेल का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से बढ़ेगी मांग तेल मंत्रालय का मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार आने की वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा होगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश के अंदर ईंधन की खपत में 70 प्रतिशत तक की कमी आई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी देश के अंदर लगा लॉकडाउन, लेकिन 2021-22 में भारत के अंदर तेल और गैस की जो खपत होगी वो पिछले 6 साल के अंदर सबसे अधिक होगी और इसकी सबसे बड़ी वजह देश में ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री सेक्टर का मजबूत होना है। आपको बता दें कि तेल आयात करने के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगले वित्त वर्ष में 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ सकती है डीजल की खपत पेट्रोलियम मंत्रालय ने आगामी वित्त वर्ष में डीजल की खपत में 13 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। वहीं जेट ईंधन की खपत में 74 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है। डीजल देश में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ईंधन है। वहीं चालू वित्त वर्ष में कुल ईंधन की मांग में 8.5 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है। वहीं एलपीजी की मांग 4.8 से घटकर 2.9 रह गई है।

News यू केन USE

ऑरा ने मिलेनियल्स के लिए नया आकर्षक कलेक्शन लॉन्च किया

नई दिल्ली। एजेंसी

डायमंड ज्वैसलरी में भारत के प्रमुख और सबसे विश्वसनीय ब्रैंड ऑरा ने डिज़ायर्ड कलेक्शन पेशकर अपने पोर्टफोलियो में नई कैटिगरी को जोड़ा है। यह कलेक्शन मिलेनियल्सस पर लक्षित है। डिज़ायर्ड की पेशकश के साथ, ऑरा ने युवा भारतीय महिला उपभोक्ताओं के लिए अपनी समकालीन ज्वैलरी रेंज का विस्तार किया है। ऑरा ब्रैंड की पेशकश के साथ ही दिशा पाटनी को ब्रैंड का एंबेसेडर बनाने की घोषणा की गई। लॉकडाउन में ऑरा ने ब्रैंड के प्रति समर्पित उपभोक्ताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी। कंपनी ने 2021 में अपने प्रॉडक्ट्स के प्रति आकर्षित होती युवा महिलाओं पर फोकस करते हुए अपने टॉपलाइन प्रॉडक्ट्स की बिक्री में सकारात्मक बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की थी। डिज़ायर्ड कलेक्शन उन फैशनेबल आधुनिक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ज्वैलरी को अपने फैशन स्टेटमेंट और स्टाइल का हिस्सा मानती हैं, जिससे उनकी शख्सियत में निखार आए। 100 से ज्यादा नए स्टाइल के साथ रोज़ गोल्ड और डायमंड्स में बेहतरीन, जबर्दस्त और विविधतापूर्ण ज्वै0लरी कलेक्शन पेश किया गया है। इस कलेक्शन को 14 कैरेट गोल्ड में बनाया गया है। इसके साथ ही इसमें ईयररिंग्स और रिंग्स लॉन्च की गई है। इस प्रॉडक्ट कैटेगरी में यह ऑरा की पहली पेशकश है।

विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं खरीद 10 प्रतिशत बढ़कर 427 लाख टन हो सकती है

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने मंगलवार को कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन के कारण रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद 9.56 प्रतिशत बढ़कर 427.36 लाख टन होने का अनुमान है। गेहूं एक प्रमुख रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) फसल है। कटाई इस महीने के अंत से शुरू होती है लेकिन अप्रैल से गति पकड़ती है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय सचिव ने रबी विपणन सत्र 2021-22 और खरीफ विपणन सत्र के चावल (रबी फसल) के दौरान गेहूं की खरीद की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए राज्य खाद्य सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की।

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का निर्यात

मोबाइल फोन्स की हिस्सेदारी सबसे अधिक

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का निर्यात नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल 2020 में 8,806 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का निर्यात हुआ है। करीब 35 फीसदी के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन्स का रहा है। कुल 3,061 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन्स भारत से निर्यात किए गए हैं। दिसंबर 2019 की तुलना में यह आंकड़ा करीब 50 फीसदी अधिक है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के मुताबिक, 'इस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभूतपूर्व चुनौतियों को पार कर लिया है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, 2019 के तहत अब इसमें मोमेंटम देखने को मिल रही है।

लॉकडाउन के दौरान बंद रहा था प्रोडक्शन

ICEA ने कहा कि पीएलआई स्कीम की वजह से कोविड काल में भी इस इंडस्ट्री ने 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है. कोविड की वजह से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बीच भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। जबकि, लॉकडाउन के दौर में करीब 45 दिनों के लिए उत्पादन बिल्कुल बंद हो चुका था। महामारी के दौरान मोबाइल फोन इंडस्ट्री ने घरेलू मांग को भी पूरा किया है। इसके बाद भी दिसंबर 2020 तक 14,000 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन्स का निर्यात भी किया गया है।

बजट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ी

निर्यात होने वाले उत्पादों पर ड्यूटीज़ और टैक्स में छूट के लिए बने RoDTEP स्कीम से इसे बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ICEA ने सरकार को भी इस बारे लिखा है कि इस सेक्टर के लिए भी RoDTEP लागू किया जाए। हालांकि, सरकार की ओर से आम बजट में इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है. सरकार ने बजट में कुछ आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ही फैसला लिया है।

निर्यात बढ़ाने सरकार ने पेश किया है पीएलआई स्कीम

केंद्र सरकार के लिए निर्यात को बढ़ावा देना एक प्रमुख एजेंडा है। यही कारण है कि सरकार ने पिछले प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव्स (PLI) स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत भारत में बनने वाले मोबाइल फोन्स के लिए अगले 5 साल में से 4 से 6 फीसदी का कैश इंसेटिव्स का लाभ मिलेगा। जिन कंपनियों को पीएलआई स्कीम के तहत मंजूरी मिलेगी, वो कंपनियों अगले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात कर सकेंगी। कुल निर्यात के हिसाब से देखें तो यह करीब 60 फीसदी होता है। सरकार ने हाल ही में पीएलआई स्कीम का दायरा आईटी प्रोडक्ट्स तक बढ़ा दिया है। सरकार चाहती है कि अगले 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का आंकड़ा 2.45 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाए।

भारत का डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों से बौद्धिक संपदा छूट प्रस्ताव पर आम सहमति बनाने का आग्रह

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों से कोविड-19 संकट से निपटने के लिये बौद्धिक संपदा पर बहुपक्षीय समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट देने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने का आग्रह किया है। भारत ने कहा कि ऐसे समय जब, महामारी के कारण लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, हम अंतहीन चर्चा करते नहीं रह सकते। डब्ल्यूटीओ में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि ब्रजेन्द्र नवनीत ने एक मार्च को आम परिषद की बैठक में कहा कि सभी सदस्य देशों के समन्वित प्रयास की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विश्व व्यापार संगठन केविड-19 संकट को जड़ से समाप्त करने में सार्थक योगदान दे सकता है और संकट की घड़ी में वास्तव में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में डब्ल्यूटीओ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। इसमें कोविड-19 महामारी से बचाव, रोकथाम या इलाज के संदर्भ में संगठन के सभी सदस्य देशों के लिये व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के कुछ प्रावधानों से छूट दिये जाने की बात कही गयी थी। ट्रिप्स जनवरी 1995 में प्रभाव में आया। यह बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों पर एक बहुपक्षीय समझौता है। इसमें कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और अघोषित सूचना या व्यापार गोपनीयता का संरक्षण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रावधानों से छूट को लेकर खुली चर्चा हुई है। इसमें छूट की अवधि और दायरा शामिल हैं। नवनीत ने कहा, "हम सदस्य देशों से छूट प्रस्तावों पर आम सहमति बनाने का आग्रह करते हैं ताकि कोविड-19 की रोकथाम से जुड़े उत्पादों का निष्पक्ष, समान और किफायती दरों पर पहुंच समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।" उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय कोविड-19 टीकों की विकासशील अर्थव्यवस्था तक पहुंच सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को 9,200 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच सकता है। नवनीत ने कहा कि टीका आने के तीन महीने बाद भी वैश्विक टीकाकरण परिदृश्य मजबूत नहीं दिख रहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि टीकाकरण की प्रगति असंतुलित और निष्पक्ष नहीं है। अभी 130 से अधिक देशों को टीके की एक भी खुराक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि छूट से न केवल अमूल्य मानव जीवन को बचाने में मदद मिलेगी बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में ग्राहकों के बीच एक भरोसा भी बढ़ेगा तथा विश्व व्यापार और वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में पुनरूद्धार की गति तेज होगी।

इंटरनेट की दुनिया में खलबली मचाने Elon Musk की एंट्री

1GB स्पीड वाला इंटरनेट लॉन्च

नई दिल्ली। इंटरनेट की दुनिया में बड़ा धमाका मचाने विश्व के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की एंट्री भारत में हो चुकी है। भारत में इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदल देने के लिए एलन मस्क की कंपनी भारत में लॉन्च हो चुकी है और अब भारत के हर इलाके में रहने वाले उपभोक्ताओं को बेहद हाईस्पीड इंटरनेट सर्विस मिल सकेगी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सर्विस अब भारत में आ गया है। यानि, स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सर्विस का प्री ऑर्डर अब आप कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर ब्रॉडबैंड वितरण का काम शुरू करने का फैसला किया है। स्टारलिंक कंपनी सीधे सीधे अंतरिक्ष से इंटरनेट के लिए सिग्नल भेजेगी लिहाजा इसकी इंटरनेट स्पीड काफी ज्यादा होने की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी सीधे सीधे रिलाइंस व्द को टक्कर देगी। स्पेस एक्स की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में भी इंटरनेट की दुनिया को बदलने का दावा किया है और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने हाईस्पीड इंटरनेट के लिए एक हजार से ज्यादा उपग्रहों की तैनाती कर दी है। स्पेसएक्स की सैटेलाइट बेस्ट इंटरनेट सर्विस काफी तेज इंटरनेट की सुविधा देने वाली है लिहाजा इसकी कीमत भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत में स्टारलिंक इंटरनेट ब्रॉडबैंड के लिए आपको 99 डॉलर यानि करीब 7300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि, स्टारलिंक कंपनी भारत के उपभोक्ताओं को अपनी सर्विस अगले साल यानि 2022 से देना शुरू करेगी मगर इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि प्री बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। भारत में स्टारलिंग की टेस्टिंग चल रही है जो बीटा फेज में है। इंटरनेट सर्विस के बारे में जानकारी देते हुए स्पेस एक्स ने कहा है कि 'आज की दुनिया में ज्यादातर आदमी वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं इसके साथ ही ज्यादातर छात्रों की पढ़ाई ही ऑनलाइन हो रही है, लिहाजा तेज इंटरनेट सर्विस होना बेहद जरूरी है और स्टारलिंक कंपनी अपने उपभोक्ताओं को तीव्र इंटरनेट स्पीड देंगे। हम उन एरिया में जल्द से जल्द इंटरनेट पहुंचा देंगे जहां तक अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंचा है।' स्पेस एक्स कंपनी ने ट्वीट में कहा है कि 'स्टारलिंक के सैटेलाइट दूसरी कंपनियों के सैटेलाइट की तुलना में पृथ्वी से 60 गुना ज्यादा नजदीक हैं, जिसकी वजह से हम बेहत तेज स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में कामयाब हो रहे हैं। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल से लेकर ऑनलाइन गेमिंग भी बेहद आसान हो जाएगी' इंटरनेट स्पीड और डिटेल्स स्टारलिंक कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी 1GBPS इंटरनेट डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देगी। इस वक्त स्टारलिंक की स्पीट 150MBPS है, जो टेस्टिंग के दौरान बढ़कर 300 ईंझ्ए हो जाएगी। वहीं, कंपनी का कहना है कि इसकी इंटरनेट का दायरा 20 मीटर से 40 मीटर के बीच का होगा। अगर आप भी स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं तो आपको कंपनी के वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करना होगा। वहीं, कंपनी ने कहा कि अगर वो शर्त के मुताबिक इंटरनेट उपलब्ध कराने में नाकाम होती है, तो उपभोक्ताओं को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप इंटरनेट लेना चाहते हैं तो आपको www.starlink.com वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप प्री बुकिंग कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश का 2021-22 का बजट 2,41,375 करोड़ रुपये का, कोई नया कर नहीं

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नवीन कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को उम्मीद है कि राज्य सरकार सुधारों की शर्त पूरी कर चालू वित्त वर्ष में बाजार से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर्ज जुटाने की मंजूरी प्राप्त कर लेगी। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा चार प्रतिशत प्रस्तावित है एवं ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित कतिपय सुधारों के करने पर इसको अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत बढ़ाने की स्वीकृत मिल सकती है। देवड़ा ने कहा,'' हमें पूरा विश्वास है कि जो भी सुधार निर्धारित किये जाएंगे उसे हम पूरा कर हम राजकोषीय घाटे के मामले में अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इसे ध्यान में रखकर बजट अनुमान तैयार किया गया है। बजट में राजकोषीय घाटा साढे चार प्रतिशत रहने का अनुमान है। देवड़ा ने टैबलेट के जरिये बजट पेश किया। इसमें आगामी अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल विनियोग की राशि 2,41,375 करोड़ रुपये है। इसमें राजस्व व्यय के अंतर्गत 1,72,971 करोड़ रूपये और पूंजीगत व्यय अंतर्गत 44,152 करोड़ रूपये के खर्च का प्रस्ताव है।'' देवड़ा ने कहा कि सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं पर अगले वित्त वर्ष में 1,12,521 करोड़ रूपये के खर्च का अनुमान है। देवड़ा ने बताया, ''वर्ष 2021-22 की कुल प्राप्तियां 2,15,954 करोड़ रूपये तथा कुल व्यय 2,17,123 करोड़ रूपये अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन का अंतर 1,169 करोड़ रूपये ऋणात्मक है एवं अंतिम शेष 5,465 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।'' उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रूपये अनुमानित है जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 8,293 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। देवड़ा ने बताया कि हमारे बजट प्रस्तावों में हमने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के विजन को मूर्तरूप देने हेतु आवश्यक प्रावधान किये हैं। साथ ही सभी जन हितैशी व विकासोन्मुखी योजनाओं को निरन्तर रखने के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गये हैं। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा 'हॉरिजोन्टल डिवोल्यूशन' के अंतर्गत राज्यों में बंटने वाले केन्द्रीय करों में से मध्यप्रदेश के लिए 7.548 प्रतितशत की हिस्सेदारी तय की गई थी। मध्यप्रदेश द्वारा 15वें वित्त आयोग को इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए अपने मूल ज्ञापन तथा अतिरिक्त ज्ञापन में ठोस तर्क प्रस्तुत किये थे। देवड़ा ने बताया कि मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए हमारी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.85 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस बढ़ोत्तरी से वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश को केन्द्रीय करों की लगभग 2,000 करोड़ रूपये अतिरिक्त राशि प्राप्त होना अनुमानित हैं उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 1,64,677 करोड़ रूपये है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां 64,914 करोड़ रूपये तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां 52,247 करोड़ रूपये अनुमानित है। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 11,742 करोड़ रूपये तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां 35,774 करोड़ रूपये अनुमानित है। देवड़ा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व में लगभग 5.05 प्रतिशत की कमी होना संभावित है। उन्होंने कहा कि आशावादी दृष्टिकोंण अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर-राजस्व में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है देवड़ा ने बताया, ''इस बजट में कोई नवीन कर लगाने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने क प्रस्ताव नहीं है।''

महामारी के बावजूद दिसंबर में कार्बन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा

पेरिस। एजेंसी

वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाईऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन में पिछले साल दिसंबर में वर्ष 2019 के इसी माह के मुकाबले हल्की वृद्धि दर्ज की गयी है। महामारी के कारण उत्सर्जन के स्तर में तीव्र कमी दिखी थी, वह कुछ समय के लिये ही थी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार तेल, गैस और कोयले के उत्पादन और उपयोग के कारण उत्सर्जन दिसंबर 2020 में इससे पूर्व वर्ष के इसी माह के मुकाबले 2 प्रतिशत अधिक रहा। पेरिस स्थित अंतर-सरकारी एजेंसी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के अभाव के कारण कई देशों में कोरोना वायरस महामारी से पहले की तुलना में अधिक उत्सर्जन देखा जा रहा है। एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फतीह बिरोल ने कहा, ''पिछले साल के अंत में उत्सर्जन में तेजी एक चेतावनी है कि हमने दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिये बहुत कुछ नहीं किया।'' उन्होंने कहा, ''अगर सरकारें उपयुक्त ऊर्जा नीतियों के साथ तेजी से आगे नहीं बढ़ती हैं, तो इससे वैश्विक उत्सर्जन में 2019 को विभाजक वर्ष बनाने का दुनिया के लिये ऐतिहासिक अवसर खतरे में पड़ सकता है।'' वैज्ञानिकों ने पूर्व में अनुमान जताया था कि सीओ2 उत्सर्जन में 2020 में 7 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इसका कारण महामारी के कारण लोगों का अपने घरों में रहना है। बिरोल ने कहा, ''हमारे पास जो आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि हम कार्बन गहन कारोबार में फिर से लौट रहे हैं।'' ग्लोबल वार्मिंग के लिये जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कार्बन डाईऑक्साइड है।

जियो ने शुरू की 5G लॉन्च की तैयारी, खरीदे 57 हजार करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दो दिन चली दूरसंचार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम) की स्पेक्ट्रम नीलामी मंगलवार को समाप्त हो गई। रिलायंस जियो ने सभी 22 सर्किल्स में स्पेक्ट्रम खरीदा है। रिलायंस जियो के खरीदे गए स्पेक्ट्रम की कुल कीमत 57123 करोड़ रुपये है। इस खरीद के बाद रिलायंस जियो के पास कुल 1717 मेगाहर्ट्ज (अपलिंक+डाउनलिंक) स्पेक्ट्रम हो जाएंगे, जो कि पहले के मुकाबले 55 फीसदी अधिक है। स्पेक्ट्रम की खरीद से रिलायंस जियो को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

5G सर्विस देने में यूज किए जा सकते हैं स्पेक्ट्रम

रिलायंस जियो ने जो स्पेक्ट्रम खरीदे हैं उसका इस्तेमाल 5G सर्विस देने के लिए भी किया जा सकता है। रिलायंस जियो ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसने स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसे अमेरिका में टेस्ट कर लिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी इसी साल 5G लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है, 'रिलायंस जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी है, भारत डिजिटल-लाइफ को तेजी से अपनाने वाला देश बन गया है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ हम डिजिटिल सेवाओं से जुड़ने वाले संभावित 30 करोड़ उपयोगकर्ताओं को बेहतरीन डिजिटल अनुभव प्रदान कर सकें। हम भारत में डिजिटल फुटप्रिंट को और विस्तार देने के लिए तैयार हैं और साथ ही 5G रोलआउट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।'

प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले मजूबत स्थिति में जियो

भारत में पांच साल में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी मंगलवार को 77,814.80 करोड़ रुपये के सपेक्ट्रम खरीदने के साथ खत्म हुई, जिसमें ज्यादातर स्पेक्ट्रम मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने खरीदा। टेलीकॉम कंपनियों ने जो स्पेक्ट्रम लिए हैं, उनकी कीमत का भुगतान अगले 18 साल में किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी टेलिकॉम कंपनियों के मुकाबले रिलायंस जियो मजबूत स्थिति में है क्योंकि जियो के पास औसतन 15.5 साल के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध हैं।

विमान ईंधन की कीमतों में 6.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि

नयी दिल्ली। एजेंसी

विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में सोमवार को 6.5 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में तेजी आ रही है, जिससे विमान ईंधन महंगा हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार एटीएफ के दाम 3,663 रुपये प्रति किलोलीटर या 6.5 प्रतिशत बढ़ाए गए हैं। इससे राष्ट्रीय राजधानी में विमान ईंधन का दाम 59,400.91 रुपये प्रति किलोलीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। फरवरी से विमान ईंधन कीमतों में यह तीसरी वृद्धि है। इससे पहले 16 फरवरी को विमान ईंधन के दाम 3.6 प्रतिशत बढ़े थे। एक फरवरी को विमान ईंधन के दाम 3,246.75 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ाए गए थे। सोमवार को ब्रेंट कच्चा तेल बढ़त के साथ 65.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह एक साल में इसका सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन कोई वृद्धि नहीं की गई। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपये और मुंबई में 97.57 रुपये प्रति लीटर है। दिल्ली में डीजल 81.47 रुपये और मुंबई में 88.60 रुपये प्रति लीटर पर है। पिछले महीने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया था। ये दोनों राज्य ईंधन पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) लेते हैं। मुंबई में शनिवार को ब्रांडेड/प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये को पार कर गया। इस समय यह 100.35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

दो महीनों की बढ़ोत्तरी के बाद फरवरी में फिर निर्यात में 0.25 प्रतिशत की गिरावट, व्यापार घाटा बढ़ा

नई दिल्ली। पिछले दो महीनों में वृद्धि दर्ज करने के बाद भारत का निर्यात फरवरी में एक बार फिर से गिर गया है। देश का निर्यात फरवरी में 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 27.67 अरब डॉलर रह गया। जबकि इससे पिछले वर्ष के इसी माह में यह आंकड़ा 27 अरब 74 करोड़ डालर रहा था। वहीं, इस दौरान आयात 6.98 प्रतिशत बढ़कर 40.55 अरब डॉलर रहा। अर्थशास्त्रियों और निर्यातकों इस गिरावट की आशंका पहले ही व्यक्त की थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंगलवार को यहां जारी एक आंकड़ों में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक कुल निर्यात 12.32 प्रतिशत गिरकर 255.92 अरब डालर रहा है जबकि वर्ष 2020 की इसी अवधि में कुल निर्यात 291.87 अरब डालर था। मंत्रालय ने बयान में कहा कि फरवरी में व्यापार घाटा बढ़कर 12.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 10.16 अरब डॉलर रहा था। अप्रैल-फरवरी के दौरान आयात भी 23 प्रतिशत घटकर 340.88 अरब डॉलर रह गया। फरवरी में तेल आयात 16.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8.99 अरब डॉलर रह गया। वहीं वित्त वर्ष के पहले 11 माह में तेल आयात में 40.18 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 72.08 अरब डॉलर रहा है। विश्लेषकों और निर्यातकों का कहना है कि मौजूदा तिमाही में आउटबाउंड व्यापार के खराब प्रदर्शन को देखते हुए अगली तिमाही में इसमें सुधार की उम्मीद नहीं है। फरवरी में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 27.13 प्रतिशत, चमड़े का 21.62 प्रतिशत, काजू का 18.6 प्रतिशत, रत्न एवं आभूषण का 11.18 प्रतिशत, इंजीनियरिंग सामान का 2.56 प्रतिशत, चाय का 2.49 प्रतिशत और कॉफी का 0.73 प्रतिशत नीचे आया। पिछले महीने में 8 प्रतिशत की गिरावट के बाद इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात का शिपमेंट 2 प्रतिशत गिर गया। इस क्षेत्र में निर्यात के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है।

शिव चरित्र देता है सफल जीवन और जनकल्याण की प्रेरणा

आशुतोष, भवानीशंकर भगवान शिव परम तपस्वी एवं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा योग साधना के शीर्षदेव हैं। उनकी आराधना से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य में शिव तत्व उपस्थित है और इसे शिव के प्रति अनुराग, भक्ति एवं आराधना से जागृत किया जा सकता है। आराधक उनके विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रखकर अपने को शिवमय कर सकता है।

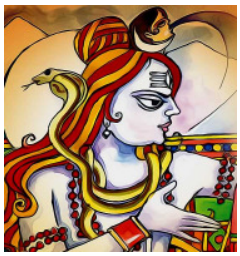

तपस्या- भगवान सदैव ही एकांत एवं निर्जन स्थान पर एकाग्र भाव से तपश्चर्या एवं ध्यान में लीन रहते हैं। इससे व्यक्ति सांसारिक भावों से दूर हो जाता है। इसके कारण संसारजनित विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं अहंकार से मुक्ति मिलती है। यह जनकल्याण का प्रथम चरण है।

न्यूनतम आवश्यकताएं- भगवान शिव शरीर पर भस्म धारण करते हैं तथा मृगछाल पहनते हैं। हाथ में जल भरने हेतु कमंडल रखते हैं तथा खड़ाऊं धारण किए हैं। उनकी आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं। इस मनोभावना के कारण व्यक्ति त्याग और असंग्रह की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे-जैसे व्यक्ति भौतिक संसाधनों की ओर प्रवृत्त होता है, वैसे-वैसे उनको प्राप्त करने एवं उपभोग करने की इच्छा बलवती होती जाती है जिसके फलस्वरूप स्पर्धा एवं संघर्ष का जन्म होता है। अतः शिव का यह स्वरूप व्यक्ति को त्याग, असंग्रह तथा बाहरी प्रदर्शन से निवृत्ति की ओर ले जाने का संदेश देता है।

सहनशीलता- भगवान शिव, नीलकंठ हैं तथा कंठ में ही सदैव नाग को धारण करते हैं। उन्होंने समुद्र मंथन से प्राप्त विष को अपने कंठ में धारण किया है, जो यह संदेश देता है कि संसार में अनेक प्रकार की विषमताएं एवं विसंगतियां विद्यमान हैं। व्यक्ति में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं। नीलकंठ स्वरूप हमें विपरीत परिस्थितियों में एवं विपरीत व्यवहार में भी अविचल रहने की प्रेरणा देते हैं।

शीतलता एवं संवेदनशीलता- चंद्र शीतलता, निर्मलता एवं प्रकाश का प्रतीक है। भस्मीभूत भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण करके सांसारिक जीवों को यह संदेश दिया है कि हम मस्तिष्क में सदैव शीतलता धारण करें, उग्रता को त्यागें, धैर्य से सभी के कथन को सुनें तथा आंतरिक निर्मलता के साथ ज्ञान प्रकाश से अन्य जीवों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें।

कल्याणकारी शिवयोग में मनेगा महाशिवरात्रि का पावन पर्व

शिव कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ दिन है महाशिवरात्रि का पावन पर्व, इस बार यह शुभ दिन 11 मार्च 2021, गुरुवार को है। इस दिन सुबह 09 बजकर 22 मिनट तक महान कल्याणकारी 'शिवयोग' भी विद्यमान रहेगा। उसके बाद सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला 'सिद्धयोग' आरम्भ हो जाएगा। शिव योग को स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त है कि जो तुम्हारे उपस्थित रहने पर कोई भी धर्म-कर्म मांगलिक अनुष्ठान आदि कार्य करेगा वह संकल्पित कार्य कभी भी बाधित नहीं होगा उसका कार्य का सुपरिणाम कभी निष्फल नहीं रहेगा इसीलिए इस योग के किये गए शुभकर्मों का फल अक्षुण रहता है।

सिद्ध योग में भी सभी आरम्भ करके कार्यसिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इन योगों के विद्यमान रहने पर रुद्राभिषेक करना, शिव नाम कीर्तन करना, शिवपुराण का पाठ करना अथवा शिव कथा सुनना, दान पुण्य करना तथा ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अतिशुभ माना गया है। इस दिन का प्रत्येक घड़ी-पहर परम शुभ रहता है। कुवांरी कन्याओं को इस दिन व्रत करने से मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों का वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा करने से जन्मकुंडली के नवग्रह दोष तो शांत होते हैं विशेष करके चंद्र्जनित दोष जैसे मानसिक अशान्ति, माँ के सुख और स्वास्थ्य में कमी, मित्रों से संबंध, मकान-वाहन के सुख में विलम्ब, हृदयरोग, नेत्र विकार, चर्म-कुष्ट रोग, नजला-जुकाम, स्वांस रोग, कफ-निमोनिया संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढती है। सुहागिन महिलाओं को इसदिन माँ पार्वती को श्रृंगार हेतु मेंहदी चढानी चाहिए और पुरुषों को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर बेलपत्र पर अष्टगंध, कुमकुम, अथवा चन्दन से राम-राम लिखकर ॐ नमःशिवाय करालं महाकाल कालं कृपालं

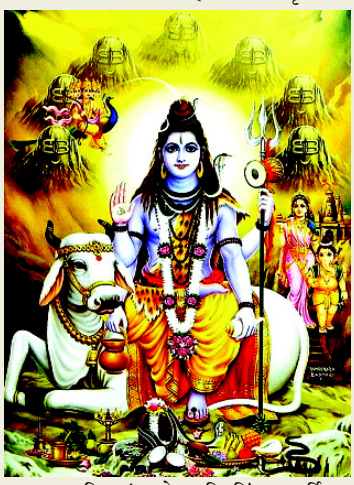

ॐ नमः शिवाय' कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए साथ ही भांग, धतूर और मंदार पुष्प तथा गंगाजल भी अर्पित हुए काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुःख हरो,दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि शंकर शंकर शंभो तव शरणं। मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढती है। भांग अर्पण से घर की अशांति, प्रेत बाधा तथा चिंता दूर होती है। मंदार पुष्प से नेत्र और हृदय विकार दूर रहते हैं। शिवलिंग पर धतूर के पुष्प-फल चढ़ाने से दवाओं के रिएक्शन तथा विषैले जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। शमीपत्र चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती, मारकेश तथा अशुभ ग्रह-गोचर से हानि नहीं होती। इसलिए श्रीमहाशिवरात्रि के एक-एक क्षण का सदुपयोग करें और शिवकृपा प्रसाद से त्रिविध तापों से मुक्ति पाएं।

शिव पूजा के दौरान भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां

1-शंख जल- भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है शिव की नहीं।

2-पुष्प- भगवान शिव की पूजा में केसर, दुपहरिका, मालती, चम्पा, चमेली, कुन्द, जूही आदि के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए।

3-करताल- भगवान शिव के पूजन के समय करताल नहीं बजाना चाहिए।

4-तुलसी पत्ता- जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया है। इसलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं होती है।

5- काला तिल- यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए।

6-टूटे हुए चावल- भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है।

7-कुमकुम- यह सौभाग्य का प्रतीक है जबकि भगवान शिव वैरागी हैं इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ता।

भगवान शिव के 12 अनमोल वचन

भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग-अलग रूपों में विद्यमान है। भगवान शिव के अनमोल वचनों को 'आगम ग्रंथों' में संग्रहित किया गया है। आगम का अर्थ ज्ञान अर्जन। पारंपरिक रूप से शैव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उप-आगम हैं।

शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र सहित अनेक ग्रंथों में अनमोल वचनों को संग्रह करके रखा गया है। उनमें से ही कुछ अनमोल मोती...

1.कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण : आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि 'कल्पना' ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या खयाल करते रहते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज्यादा योगदान है।

2.बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान : आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती और शिव के बीच जो संवाद होता है उसे 'विज्ञान भैरव तंत्र' में संग्रह किया गया है। इसमें ध्यान की 112 विधियां संग्रहीत है।

3.शून्य में प्रवेश करो : विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वतीजी से कहते हैं, 'आधारहीन, शाश्?वत, निश्?चल आकाश में प्रविष्ट होओ।' वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं- 'वामो मार्गः परमगहनो योगिताम्प्यगम्यः' अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। -मेरुतंत्र...भगवान शिव के योग को तंत्र या वामयोग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठयोग की है।

4.आदमी पशुवत है : मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायबघर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है।

5.मरना सीखो : यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है।

6.गायत्री मंत्र : 'गायत्री-मंजरी' में 'शिव-पार्वती संवाद' आता है जिसमें भगवती पूछती हैं- 'हे देव! आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है?' उन्होंने उत्तर दिया- 'गायत्री ही वेदमाता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है।'

7.जीवन को सुखमयी बनाने के लिए : भोजन और पान (पेय) से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु-बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाएं।

8.प्रकृति का सम्मान करो : प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सबकुछ वही कर रहे हैं।

9.योग की शक्ति को समझो

विस्मयो योगभूमिकाः। स्वपदंशक्ति। वितर्क आत्मज्ञानमू।

लोकानन्दः समाधिसुखम्। -शिवसूत्र

अर्थात : विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है।

10.अपनी तरफ देखो- न तो पीछे, न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। -शिवसू?त्र

11.माया को समझो :

आत्मा चित्तम्। कलादीनां तत्वानामविवेको माया।

मोहावरणात् सिद्धिः। जाग्रद् द्वितीय करः। -शिवसूत्र

अर्थात आत्मा चित्त है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जाग्रत योगी को, सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है।

12.अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की जरूरतों को एक तरफ छोड़ दो।- शिवसूत्र

कोरोना वैक्सीनेशन के लिए समयसीमा खत्म, अब चौबीसों घंटे होगा टीकाकरण : स्वास्थ्य मंत्री

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने कोरोना रोधी टीके लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए समयसीमा खत्म कर दी है। अब नागरिक चौबीस घंटे सातों दिन अपनी सुविधानुसार टीके लगवा सकते हैं। इससे पहले जब 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला था तब हर केंद्र पर सुबह 9 बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय वैक्सीनेशन के लिए फिक्स था।

स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ़्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता समाप्त कर दी है। देश के नागरिक अब 24x7अपनी सुविधानुसार टीका लगवा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके समय की कीमत बखूबी समझते हैं।

देश भर में कोविड-19 टीके की अब तक 1.54 करोड़ खुराक लाभार्थियों को दी गई है। इस आंकड़े में मंगलवार को दी गई 6,09,845 खुराक भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने अस्थायी आंकड़े में यह जानकारी दी। कोविड-19 का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के साथ शुरू हुआ था। वहीं, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था।

इसके बाद, एक मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि शाम सात बजे तक के अस्थायी आंकड़े के मुताबिक अब तक टीके की कुल 1,54,61,864 खुराक दी जा चुकी हैं।

इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,34,981 लाभार्थी और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के 60,020 लाभार्थी भी शामिल हैं। मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण के 46वें दिन मंगलवार को शाम सात बजे तक कुल 6,09,845 लोगों को टीके की खुराक दी गई। इनमें 5,21,101 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई, जबकि 88,744 स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई।

Bitcoin में फिर आया उछाल

इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए तैयार है क्रिप्टोकरेंसी

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले सप्ताह बॉण्ड रूट के ठंडे रहने के बाद बिटकॉइन ने सोमवार को एक बार फिर 7 प्रतिशत की उछाल भरी है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सिटी ग्रुप का कहना है कि यह उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे पसंदीदा मुद्रा बन सकती है। सिटी ग्रुप के मुताबिक हाल ही में टेस्ला और मास्टरकार्ड के बिटकॉइन को स्वीकार करने के बाद इसका मुख्यधारा के लेनदेन के रूप में बड़ी मात्रा में परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है।

गोल्डमैन सैक्स ने शुरू की डेस्क

बिटकॉइन की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच गोल्डमैन सैक्स ने अपनी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग डेस्क फिर से शुरू कर दी है। अगले सप्ताह से इस डेस्क के माध्यम से ग्राहकों के साथ बिटकॉइन के लिए सौदा शुरू होने की संभावना है। रॉयटर ने इस बारे में जानकारी दी है।

वहीं सिटी ग्रुप के मुताबिक फरवरी में 58,354 डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने वाली बिटकॉइन भविष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पसंदीदा मुद्रा बन सकती है।

बड़े निवेशकों की बढ़ी रुचि

सिटी के विश्लेषकों का कहना है कि बिटकॉइन की प्रगति के रास्ते में जोखिम और रुकावटें हैं लेकिन इसे लेकर जो अवसर सामने आ रहे हैं उनके मुकाबले इन बाधाओं का परीक्षण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि बिटकॉइन एक टिपिंग पॉइंट पर है जहां से यह इंटरनेशनल ट्रेडिंग में प्रवेश कर सकती है। बिटकॉइन पहले छोटे निवेशकों के सहारे बढ़ रही थी लेकिन पिछले एक दशक में क्रिप्टोकरेंसी में बड़े और संस्थागत निवेशकों की रुचि आने से इसने जोर पकड़ा है। इसमें हाल ही में टेस्ला के एलन मस्क और मास्टरकार्ट की एंट्री बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है। टेस्ला के निवेश के बाद बिटकॉइन में काफी तेज उछाल देखा गया था।

महिला इंजीनियरों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए गूगल के सहयोग से चल रहा है प्रोग्राम

बंगलौर। एजेंसी

प्रसिद्ध एड.टेक प्लेटफार्म और एनसीई ग्रुप की कंपनी, टैलेंट स्प्रिंट ने तीसरे समूह के महिला इंजीनियर्स प्रोग्राम (डब्लूई) के लांच करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में गूगल का सहयोग भी शामिल है। टैलेंट स्प्रिंटड ब्लूई का गठन साल 2019 में टेक इंडस्ट्री में फैली लैंगिक असमानता को दूर करने केउद्देश्य से किया गया था। पहले के दो समूहों को इंडस्ट्री ने जिस तरह से प्रतिसाद मिला उसको देखते हुए, अब तीसरे समूह में 500 प्रतियोगियों को जगह देने की कोशिश की गई है। इस समूह में देशभर की प्रथम वर्ष की महिला विद्यार्थियों को लक्ष्य में रखा गया है, जिसकी शुरुआत मई 2021 से की जाएगी। यह बात सर्वविदित है कि कम्प्यूटर युग के शुरुआती दिनों में महिलाओं की काफी अहम् भूमिका रही थी। लेडी ऐडा लवलेस और एडमिरल ग्रेस हॉपर, दोनों महिलाएं क्रमशः दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर टेस्टर रही थीं। इस शुरुआती रोल मॉडल होने के बावजूद महिला प्रोफेशनल्स की भूमिका टेक्नोलॉजी सेक्टर में कम होती गयी और आज के ग्लोबल टेकवर्क फोर्स में महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ 26% रह गयी है। इस लैंगिक असामनता को दूर करने के उद्देश्य से टैलेंट स्प्रिंट वी प्रोग्राम ने देशभर से प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग महिलाओं को चुनने, प्रशिक्षित करने और उनको तैयार करने का बीड़ा उठाया है। इन प्रतिभाशाली ऐकडेमिक महिलाओं को, जो विभिन्न सामाजिक बैक ग्राउंड से आती हैं,सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ.साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है।

जियो यूजर्स को बड़ी खुशखबरी

अब बिना सिम कार्ड के कर सकेंगे कॉल, जानें क्या है eSIM

नई दिल्ली। रिलायंस जियो हमेशा से अपने बेहतरीन प्लान और ऑफर के साथ लोगों को लुभाता रहा है। जियो के बेहतरीन प्लान की वजह से ही ये टेलीकॉम कंपनी इतने कम समय में देश की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बन गई है। यूजर्स को अपने फ्री कॉलिंग और डेटा प्लान से आकर्षित करने के बाद जियो ने अब एक और नया फीचर पेश किया है।

जियो ने अपने ग्राहकों के लिए ाएश्र सपोर्ट डिवाइज पेश किया है। ईसिम या इंबेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की मदद से यूजर बिना सिम के सीधे अपने फोन से कॉल कर सकता है। इस ईसिम को सीधे फोन में एंबेड कर डायरेक्ट कॉलिंग की जा सकती है। टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को ईसिम डिवाइज उपलब्ध करा रही है। इस ईसिम की मदद से फोन का स्पेस क सेविंग भी होती है। इस eSIM की मदद से यूजर फ़ोन में बिना सिम डाले भी कॉलिंग कर सकते है। जियो स्टोर पर उपलब्ध अगर आप जियो यूजर हैं और ईसिम की सुविधा चाहते हैं तो आप जियो स्टोर पर जाकर ले सकते हैं। जियो सिम लेने के लिए रिलायंस डिजिटल स्टोर या जियो स्टोर पर जाना होगा। वहीं फोटो आईडी और पहचान पत्र दिखाकर आप ले सकते हैं। वहीं नए जियो eSIM कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने फोन में नया फीचर अपलोड करना होगा। अगर आप चाहे तो अपने फिजिकल सिम को ईसिम में बदल सकते हैं। आप एक एसएमएस भेजकर अपने नॉर्मल सिम को eSIM में चेंज कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपको फोन ईसिम को सपोर्ट करता हो। ईसिम के एक्टिवेट होते ही आप बिना सिम कार्ड के कॉलिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

दिवाला प्रक्रिया वाली कंपनियों के खिलाफ 'चेक बाउंस' का मामला नहीं चल सकता : न्यायालय

नयी दिल्ली। एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के खिलाफ न तो चेक बाउंस का मामला शुरू किया जा सकता है और न ही इसे जारी रखा जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी कंपनियों को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधान के तहत संरक्षण मिला हुआ है। इसके साथ ही न्यायालय ने इन कंपनियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने चेक बाउंस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर रोक का लाभ निदेशकों या चेक पर हस्ताक्षर करने वालों को नहीं दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में उनके खिलाफ आपराधिक मामला जारी रहेगा। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह कानूनी मुद्दा आया कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138/141 (चेक बाउंस् मामला) के तहत प्रक्रिया जारी रखने को आईबीसी की धारा 14 के रोक के प्रावधान के तहत संरक्षण मिला हुआ है। आईबीसी के तहत किसी कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू होते ही उसे धारा 14 के तहत सांविधिक संरक्षण मिल जाता है। साथ ही उसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया भी रुक जाती है। पीठ में न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसफ भी शामिल थे। पीठ ने बंबई और कलकत्ता उच्च न्यायालय के उन फैसलों पर असहमति जताई जिनमें यह व्यवस्था दी गई थी कि आईबीसी के तहत दिवाला प्रक्रिया वाली कंपनियों के खिलाफ चेक बाउंस का मामला जारी रखा जा सकता है।

डाइनआउट के ग्रेट इंडियन रेस्तरा फेस्टिवल के चलते इस मार्च मिलेगी 50% की वास्तविक छूट

मौजूदा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को डाइनआउट पे का उपयोग करके 15% की अतिरिक्त छूट

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रत्येक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैम्पेन को अक्सर कस्टमर्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा डाइनिंग आउट और रेस्तरा टेक सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म 'डाइनआउट' अपने यूजर्स से यह वादा करता है कि रेस्तरा के बिलों पर फ्लैट 50ः छूट की घोषणा के पीछे कोई छिपी हुई टर्म्स तथा कंडीशंस नहीं हैं। उन्होंने भारत के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित एन्युअल रेस्तरा फेस्टिवल, डाइनआउट ग्रेट इंडियन रेस्तरा फेस्टिवल जीआईआरएफ (उ्रंह्) के 6 वें एडिशन की घोषणा की है, जिसे 26 फरवरी से 31 मार्च, 2021 तक 20 प्रमुख शहरों में 10,000 अग्रणी रेस्तरा में लागू किया जाएगा। इस फेस्टिवल में भाग लेने वाले कुछ लोकप्रिय चेन्स हैं एस कैफे, इंदौर किचन, कॉन्सटेलेशन, द क्रिएटिव किचन, हाउस ऑफ माल्ट्स, द एटीन, द पियानो प्रोजेक्ट, पिज्जा हट, बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन, कैफे दिल्ली हाइट्स और भी अन्य।

वर्ष 2020 रेस्तरा इंडस्ट्री के लिए बंदी, साथ ही आय के प्रति नुकसान का वर्ष था। डाइनआउट का उद्देश्य यूजर्स को जीआईआरएफ (GIRF) के साथ भोजन करने के लिए एक बार फिर रेस्तरा आने की शुरुआत करने और रेस्तरा इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करने में मदद करना है। साधारण तौर पर यह भारतीयों को अपने पैसे बचाने की सरल अंतर्दृष्टि और ताजा तथा गरमागर्म भोजन परोसे जाने की पुष्टि करता है। उनका 'डाइनआउट पर देखो' कैम्पेन यूजर्स को बताता है कि वे दूसरों के विपरीत यानि नए युग के लुभाने वाले एएसएमआर (ऑटोनोमस सेंसरी मेरीडियन रिस्पॉन्स) कंटेंट द्वारा दिए जाने वाले 100 रूपए की छूट के बजाए रियल डील्स पर 50ः छूट देना चाहते हैं। जीआईआरएफ (GIRF) के वर्तमान एडिशन पर टिप्पणी करते हुए, डाइनआउट के सीईओ और को-फाउंडर, श्री अंकित मेहरोत्रा कहते हैं, 'हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यूजर्स को हमारे द्वारा की गई 50% छूट की घोषणा से अवगत कराना है, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन बिक्री के युग में ब्रांड्स अक्सर बड़ी छूट की घोषणा करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं देते हैं, इसके परिणामस्वरूप कस्टमर्स ऐसे ब्रांड्स के प्रति अपना विश्वास खो देते हैं। 'डाइनआउट पर देखो' इस अंतर को कम करता है और रेस्तरा के बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असीमित परिणामों के साथ यूजर्स के मन में विश्वास को दृढ़ और सक्षम बनाता है। इसके अलावा, हमने पिछले साल की तुलना में 40ः अधिक यूजर्स को इस वेलेंटाइन डे पर रेस्तरा में समय व्यतीत करते देखा। इसका अर्थ है कि वर्ष 2021 हम सभी के लिए बेहतर वर्ष होगा।

जनवरी में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 7.6 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ टन पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन जनवरी 2021 में 7.6 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ टन पर पहुंच गया। विश्व इस्पात संघ (वर्ल्ड स्टील) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इससे पिछले साल के समान महीने में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 93 लाख टन रहा था। वर्ल्ड स्टील की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी में 64 देशों का इस्पात उत्पादन 4.8 प्रतिशत बढ़कर 16.29 करोड़ टन पर पहुंच गया। जनवरी में इस्पात उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर कायम रहा। चीन का कच्चे इस्पात का उत्पादन माह के दौरान सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत बढ़कर 9.02 करोड़ टन पर पहुंच गया। जनवरी, 2020 में चीन का उत्पादन 8.43 करोड़ टन रहा था। बीते माह जापान का इस्पात उत्पादन 3.9 प्रतिशत घटकर 79 लाख टन रहा गया। समीक्षाधीन महीने में अमेरिका का इस्पात उत्पादन भी घटकर 69 लाख टन रह गया, जो जनवरी, 2020 में 77 लाख टन रहा था। आंकड़ों के अनुसार, रूस का कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़कर 67 लाख टन पर पहुंच गया। जो इससे पिछले साल के समान महीने में 60 लाख टन रहा था। इसी तरह दक्षिण कोरिया का इस्पात उत्पादन भी 58 लाख टन से बढ़कर 60 लाख टन पर पहुंच गया। तुर्की का उत्पादन 30 लाख टन से बढ़कर 34 लाख टन पर पहुंच गया।

मोबाइल ऐप ने कीमतों के डेटा के संग्रह में सुधार लाया: सरकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने रविवार को कहा कि इस साल जनवरी से मोबाइल ऐप की शुरुआत के बाद दैनिक आधार पर 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों के डेटा संग्रह में सुधार हुआ है। उपभोक्ता मामलों का विभाग चावल, गेहूं, गेहूं का आटा, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, दूध, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पती, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पॉम ऑयल, गुड़, चाय, नमक, आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों की निगरानी करता है। राज्य सरकारों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के माध्यम से देश भर के 127 केंद्रों से मूल्य का डेटा एकत्र किया जा रहा है। विभाग ने एक बयान में कहा, ''दैनिक कीमतों की रिपोर्टिंग में आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक मोबाइल ऐप पेश किया। इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और अनुमानित विश्लेषण में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिये मोबाइल ऐप ने खुदरा और थोक मूल्यों के बारे में प्रभावी वास्तविक समय की जानकारी देनी शुरू कर दी है।''

पीएफ ब्याज दर घटाने की तैयारी, जल्दी हो सकता है ऐलान

नई दिल्ली। एजेंसी

महंगे पेट्रोल-डीजल, LPG की बढ़ती कीमतों और CNG, PNG की महंगाई के बाद अब एक और झटका झेलने के लिए तैयार हो जाइए। वित्त वर्ष 20-21 में EPF के ब्याज में एक बार फिर कटोती होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो 6 करोड़ से ज्यादा सैलरीड क्लास के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अबतक EPF सब्सक्राइबर्स जो पिछले साल तक ब्याज नहीं मिलने को लेकर परेशान थे, अब उन पर दोहरी मार पड़ने वाली है।

EPF पर मिलने वाला ब्याज घटेगा!

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना संकटकाल में लोगों ने काफी बड़ी संख्या में EPF निकासी की है, इस दौरान अंशदान में भी कमी आई है। जिसके चलते Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) दरों में कटौती का फैसला कर सकता है। नई दरों पर फैसला करने के लिए कल 4 मार्च को EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक होगी। ऐसे माहौल में दरों में कटौती तय मानी जा रही है।

4 मार्च को होगा ब्याज दरों पर फैसला

वित्त वर्ष 2020 में EPFO की कमाई पर बुरा असर पड़ा है। EPFO के ट्रस्टी के ई रघुनाथन ने बताया कि उन्हें बताया गया है कि 4 मार्च को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक श्रीनगर में होगी। उनको मिली ई-मेल में ब्याज दरों को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 परसेंट ब्याज देना का ऐलान किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पहले कहा था कि 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष में दो किस्तों में 8.5 परसेंट ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यानी 8.15 परसेंट इन्वेस्टमेंट से और 0.35 परसेंट ब्याज का भुगतान इक्विट से किया जाएगा।

EPF पर 7 साल में सबसे कम ब्याज

वित्त वर्ष 2020 में EPF पर 8.5 परसेंट का ब्याज मिला, जो कि 7 सालों में सबसे कम ब्याज है। इसके पहले वित्त वर्ष 2013 में EPF पर ब्याज दरें 8.5 परसेंट थीं। पिछले साल मार्च में EPFO ने ब्याज को रिवाइज किया था। इसके पहले वित्त वर्ष 2019 में EPF पर 8.65 परसेंट ब्याज मिलता था। EPFO ने वित्त वर्ष 2018 में 8.55 परसेंट ब्याज दिया था, जो कि इसके पहले वित्त वर्ष 2016 में ये 8.8 परसेंट था. इसके पहले वित्त वर्ष 2014 में ये 8.75 परसेंट था। आपको बता दें कि देश भर में EPF के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं. वित्त वर्ष 2020 में भी इन करोड़ों लोगों को KYC में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में देरी हुई थी। उसके बाद अब अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा।

ऑटो पार्ट रिटेलर्स और वर्कशाप की दिक्कतें अब दूर हुई

ऑटोमोबाइल सर्विस प्रोवाइडर गोमैकेनिक ने इंदौर में फ्रैंचाइज़ी आउटलेट शुरू किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में टेक्नोलॉजी-एनेबल्ड मल्टी-ब्रांड कार वर्कशॉप्स के सबसे बड़े नेटवर्क, गोमैकेनिक ने अपने गोमैकेनिक स्पेयर्स फ्रैंचाइज़ी - परफेक्ट ऑटो स्पेयर्स - के लॉन्च की घोषणा की। गोमैकेनिक ने हाल ही में अपने नए ब्रांड – गोमैकेनिक स्पेयर्स - के साथ ऑटोपार्ट्स बाजार में कदम रखा है और अपने मल्टी ब्रांड की पूरी रेंज को इस फ्रैंचाइज़ी आउटलेट के ज़रिये वितरित करेगा। उपलब्ध ब्रांड में गोमैकेनिक स्पेयर्स, मोबिल, गल्फ, मॉनरो, बॉश, वैलिओ, प्यूरोलेटर, लिवगार्ड, ल्युमैक्स, लुक, एनजीके, सुब्रोस और यूरोरिपार आदि शामिल हैं।

इंदौर में गोमैकेनिक स्पेयर्स फ्रेंचाइज़ी के लॉन्च के साथ, ब्रांड का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपने स्पेयर पार्ट्स बिजनेस का विस्तार करना है और उच्च गुणवत्ता वाले ऑटोपार्ट्स की धीमी आपूर्ति की समस्या को हल करना है। ब्रांड अब मौजूदा और भविष्य के स्पेयर पार्ट्स रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और वर्कशॉप मालिकों की जरूरतों को पूरा करेगा। फ्रैंचाइज़ी आउटलेट सभी शीर्ष ब्रांड के सही पार्ट्स की आपूर्ति करेगा और सभी प्रमुख मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के साथ गोमैकेनिक की राष्ट्रव्यापी भागीदारी के आधार पर सर्वोत्तम मार्जिन और छूट प्रदान करेगा।

फ्रैंचाइज़ी स्टोर के लॉन्च के अवसर पर, गोमैकेनिक के सह-संस्थापक, श्री नितिन राणा ने कहा कि 'हम हाल के दिनों में अपने अन्य आउटलेट्स से मिली प्रतिक्रिया से रोमांचित हैं। इंदौर हमारे लिए एक नया बाजार है, लेकिन हमारे उद्योग को लेकर अनुभव और एक्सपोजर बताता है कि यह हमारे जैसे व्यवसायों के लिए एक उच्च-संभावना वाला, बहुत महत्वपूर्ण बाजार है। हमारा उद्देश्य हमारे सभी ग्राहकों को तेजी से और किफायती समाधान प्रदान करना है। लॉकडाउन के दौरान भी होने वाली वृद्धि को देखते हुए, हमें भरोसा है कि हम अपना काम सफलता के साथ कर पायेंगे।'

विदेशी मुद्रा भंडार 16.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 583.865 अरब डॉलर पर

मुंबई। एजेंसी

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 16.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 583.865 अरब डॉलर हो गया। भारती रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले 12 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 24.9 करोड़ डॉलर घटकर 583.697 अरब डॉलर रह गया था। 29 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार 590.185 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पांच फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के बढ़ने की वजह से मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। विदेशीमुद्रा परिसंपत्तियां, कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में एफसीए 1.155 अरब डॉलर बढ़कर 542.106 अरब डॉलर हो गयी। एफसीए को दर्शाया डॉलर में जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्रा सम्पत्ति भी शामिल होती हैं। आंकड़ों के अनुसार देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 97.7 करोड़ डॉलर घटकर 35.25 अरब डॉलर रह गया। देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में मिला विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर घटकर 1.508 अरब डॉलर रह गया। आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा भंडार भी 40 लाख डॉलर घटकर 5.002 अरब डॉलर रह गया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।